760 लाख मी. टन सीमेंट की मांग का पूर्वानुमान लगाया है। सीमेंट उद्योग विकास परिषद इस लक्ष्य से प्राय: सहमत है और सुझाव दिया है कि सीमेंट उद्योग को 1996-97 तक लगभग 770 लाख मी. टन उत्पादन का लक्ष्य रखना चाहिए।

विकास परिषद ने उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है, जैसे कि कोयले/लिग्नाइट का पर्याप्त आवंटन, कोयले की गुणवत्ता में सुधार कोयले का आयात, सीमेंट/कोयले की तुलाई के लिए माल डिब्बों की आपूर्ति में वृद्धि, बेहतर विद्युत आपूर्ति, दानेदार धातु कचरा फ्लाई एश, खड़िया मिट्टी तथा अन्य विशिष्टियों की अधिक आपूर्ति सीमेंट खंगड़ के निर्यात के लिए प्रोत्साहन तथा अतिरिक्त सुविधाएं, बाजार विकास तथा सहायता के लिए सड़कों, नहरों, भवनों आदि में कंक्रीट का अधिक प्रयोग तथा ऊर्जा संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण हेतु संयंत्रों और उपकरणों के अधिष्ठापन के लिए प्रोत्साहन।

**राज्यों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्रदान किया जाना**

3147. श्री आस मोहम्मद:
श्री ईश दत्त यादव:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है,

(ख) यदि हां, तो इस निधि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बजट अनुमान 1994-95 में 700.00 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है। इसमें से, राष्ट्रीय नवीकरण निधि से राज्यों को 150 करोड़ रु. वित्तीय सहायता के रूप में दिये गये हैं जो कर्मचारियों के प्रतिपूर्ति पैकज और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता अनुदान की संचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात राज्यों को सहायता की राशि जारी की जाएगी।

**छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्ताव**

3148. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों से वर्षवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है और किन-किन बड़े उद्योगों को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने के लिए अब तक अनुमति मांगी गई है; और

(ग) सरकार ने अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है तथा बाकी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मशीनों के पुर्जों के निर्माण के लिए अनिवासी भारतीय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसका अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें 25.12 लाख रु. की इक्विटी अन्तर्ग्रस्त है।

**Proposals from Gujarat for declaring some districts as industrially backward**

3149. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Gujarat Government has proposed to the Union Government to declare some of its districts as industrially backward districts under the new industrial policy;

(b) if so, the names of these proposed districts; and

(c) the decision taken by the Union Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.